

# हैदराबाद मुठभेड़ : जांच रिपोर्ट तेलंगाना हाईकोर्ट को भेजी

■ नई दिल्ली (भाषा)।

उच्चतम न्यायालय ने हैदराबाद में एक पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक दुष्कर्म तथा हत्या मामले के चार आरोपियों की कथित मुठभेड़ की जांच से संबंधित आयोग की सीलबंद रिपोर्ट को साझा करने का शुक्रवार को आदेश दिया तथा आगे की कार्रवाई के लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय के पास भेज दिया।

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान के उस अनुरोध को टुकरा दिया कि तीन-सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में रखी जाए। पीठ ने कहा, यह (रिपोर्ट) मुठभेड़ मामले से संबद्ध है। इसमें यहां रखने जैसी कोई बात नहीं है। आयोग ने किसी को दोषी पाया है। हम मामले को उच्च न्यायालय के पास भेजना चाहते हैं। हमें मामले को वापस उच्च न्यायालय के पास भेजना पड़ेगा, हम इस मामले की निगरानी नहीं कर सकते। एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी गई है। सवाल यह है कि क्या उचित कार्रवाई की जाए। उन्होंने कुछ सिफारिशें की हैं।

■ सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों से भी रिपोर्ट साझा करने का दिया आदेश

■ पशु चिकित्सक के रेप व मर्डर के चारों आरोपितों के एनकाउंटर का मामला

पीठ ने कहा, हम आयोग सचिवालय को दोनों पक्षों को रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश देते हैं। इससे पहले पीठ ने आयोग की सीलबंद लिफाफे वाली रिपोर्ट कुछ वक्त के लिए वकीलों के साथ साझा करने से इनकार कर दिया था। चार आरोपियों के मुठभेड़ में मारे जाने की जांच कर रहे आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश वी एस सिरपुरकर ने की है। हालांकि, न्यायालय ने रजिस्ट्री को पीठ के न्यायाधीशों को रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। सीजेआई ने वकीलों के साथ कुछ वक्त के लिए रिपोर्ट साझा न करने का निर्देश देते हुए कहा था, पहले हमें रिपोर्ट पढ़ने दी जाए। इससे पहले शीर्ष न्यायालय ने

गत वर्ष तीन अगस्त को आयोग को मुठभेड़ मामले पर अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए छह महीने का और समय दिया था।

सिरपुरकर समिति का गठन 12 दिसंबर 2019 को हुआ था और उसे उन परिस्थितियों की जांच करने का जिम्मा सौंपा गया, जिसके चलते मुठभेड़ हुई। उसे अपनी रिपोर्ट छह महीने में सौंपनी थी। समिति का गठन करते हुए उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में चल रहे मुकदमों की सुनवाई पर रोक लगा दी थी।

तेलंगाना पुलिस ने कहा था कि आरोपी मुठभेड़ में मारे गए। यह घटना सुबह करीब साढ़े छह बजे हुई थी जब आरोपियों को जांच के लिए घटनास्थल ले जाया जा रहा था। चारों आरोपियों मोहम्मद आरिफ, चिटाकुंटा चेन्नाकेश्वरुलु, जोलु शिवा और जोलु नवीन को नवंबर 2019 में एक पशु चिकित्सक के सामूहिक दुष्कर्म तथा हत्या मामले में पकड़ा गया था। चारों आरोपियों को हैदराबाद के समीप एनएच-44 पर कथित मुठभेड़ में गोली मार दी गई थी। इसी राजमार्ग पर 27 वर्षीय युवती का जला हुआ शव मिला था।

# पनवा का आरोप-चेयरमैनी छोड़ने का द आप ने ढाई साल पुराने केस में बेटे को क

भास्कर न्यूज | संगरूर

ब्लॉक समिति भवानीगढ़ के कांग्रेसी चेयरमैन वरिंदर पनवा के बेटे की गिरफ्तार के बाद जेल भेजने के मामले में राजनीति गरमा गई है। पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने जेल में पहुंच पनवा के बेटे कुलजीत सिंह से मुलाकात की। वहीं, वरिंदर पनवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि आप नेता की ओर से उस पर चेयरमैन पद छोड़ने का दबाव बनाने के मकसद से ढाई साल पुराने मामले में बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जबकि आप के जिला प्रधान ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है।

ब्लॉक समिति भवानीगढ़ के चेयरमैन वरिंदर पनवा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 3 अगस्त 2019 को थाना सिटी संगरूर में उनके बेटे कुलजीत सिंह सहित 18 लोगों पर धारा 307 का मामला दर्ज किया गया था। बाद में धारा 307 को 336 में तबदील कर दिया गया था। कुछ समय बाद ही दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। दोनों पक्षों ने पुलिस से मामले

कहा-मामले में हो गया था समझौता, अब सभी नामजद युवकों



संगरूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाते वरिंदर पनवा।

भास्कर

को रद्द करने की सिफारिश की थी लेकिन उस समय पुलिस ने मामले को रद्द करने का आवेदन कोर्ट में नहीं दिया था, जिस कारण मामला लंबित चल रहा था। सरकार बदलने के बाद आप नेता उस पर चेयरमैन पद छोड़ने का दबाव बनाने लगे। उसने चेयरमैन पद से इस्तीफा नहीं

दिया, जिस कारण उसे अंजाम भुगतने की धमकियां दी गईं। अब मामले में नामजद सभी युवकों को छोड़ सिर्फ उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। 16 मई को पुलिस ने उसके बेटे कुलजीत सिंह को गिरफ्तार कर एक दिन का रिमांड हासिल किया व बाद में उसे जेल भेज दिया गया है।

चेयरमैनी न छोड़ने की भी

पनवा ने आरोप लगाया कि गिरफ्तार राजनीतिक दबाव अब भी उसे आप नेताओं के न छोड़ने पर परिवार पर झुंकी धमकियां दी जा रही हैं। पूरी तरह कांग्रेस को समर्पित माता गांव की मौजूदा सरपंच उसके चेयरमैन पद का का

किसी ने भी चेयरमैन

वहीं, कांग्रेसी वरिंदर पनवा लगाए गए आरोपों पर आप के जिला प्रधान गुरमेल सिंह आरोपों को बेबुनियाद बताया कहा कि आम आदमी पार्टी की नीति में विश्वास नहीं है किसी पर भी चेयरमैन

## **NHRC appoints retired IAS, IPS as rapporteurs in all states, to serve as its eyes & ears**

<https://theprint.in/india/governance/nhrc-appoints-retired-ias-ips-as-rapporteurs-in-all-states-to-serve-as-its-eyes-ears/962478/>

The National Human Rights Commission (NHRC), it is learnt, has appointed retired IAS and IPS officers as 'special rapporteurs' across all states/Union territories (UTs) to serve as its "eyes and ears". The rapporteurs will "examine, monitor, evaluate, advise and report" human rights violations in the states, ranging from communal riots to LGBT communities.

The NHRC has been recruiting special rapporteurs for years, but all states/UTs were not always covered and they were appointed on need basis, a senior NHRC official told ThePrint on condition of anonymity.

In the fresh exercise, the statutory body has appointed 15 rapporteurs, of which three are former IAS officers and 12 are former IPS officers who retired as director generals of police (DGPs) or held senior positions in the central and state governments. The list was released last Friday.

Some rapporteurs have been given charge of more than one state or UT, the NHRC official said.

The decision was conveyed to the appointees in a communication from the NHRC, which ThePrint has accessed.

According to the communication, the appointees have been directed to report on issues ranging from communal riots, urban terrorism, crossborder terrorism, trafficking, violence against Scheduled Castes/Scheduled Tribes (SC/STs) and Other Backward Classes (OBCs), to "all matters related to transgenders and LGBT [Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender] rights" as well as tribal welfare and so on.

The French word 'rapporteurs' translates to 'investigators', the communication adds.

Also Read: Govt order promoting IPS officer & junior IAS officers to same rank 'unprecedented', say bureaucrats

### **Primary responsibilities**

The "primary responsibility" of the rapporteurs, according to the communication, is to "examine, monitor, evaluate, advise and report on human rights problems through activities undertaken by special procedure, conducting visits and providing advice on emerging issues from the perspective of human rights".

"As the commission is based in Delhi, it is not possible for it to be present in different parts of the country to ascertain the position of human rights in these areas," it says. "In

order to ensure the reach of the commission to all regions of the country, it has decided to engage special rapporteurs who function as the eyes and ears of the commission.”

Over the past few years, the NHRC has sent its teams to various states to probe and submit reports on political violence, incidents of communal tension, and some cases of human rights violations.

In 2021, the NHRC sent a team to West Bengal to investigate incidents of violence after the assembly elections. Regional parties, including Chief Minister Mamata Banerjee’s Trinamool Congress, had accused the NHRC-led committee appointed by the Calcutta High Court to look into the alleged political killings, of political bias.

Members of the committee had submitted a report to the high court recommending a probe by the CBI. However, the Mamata Banerjee government submitted an affidavit in court countering the NHRC report.

According to NHRC data, in 2021, it received 38.2 per cent of its total complaints from Uttar Pradesh, followed by 7 per cent from Delhi, and 5 per cent each from Odisha, Bihar and West Bengal.

However, the senior NHRC official quoted earlier said that most of the body’s counterparts in the states are lying “defunct”.

“The state human rights commissions (SHRCs) are almost defunct in most states. The state government is generally averse to the idea of fresh appointments there, and common people do not have faith in those institutions anymore,” the official added. “The SHRCs are mostly seen as biased. We have seen in many cases, states refusing to comply with the recommendations of the SHRC, but in the case of NHRC, they generally accept.”



## **NHRC asks union and state govts to take action on Chakma, Hajong citizenship as directed by SC**

<https://arunachaltimes.in/index.php/2022/05/21/nhrc-asks-union-and-state-govts-to-take-action-on-chakma-hajong-citizenship-as-directed-by-sc/>

The National Human Rights Commission (NHRC) has requested the union government and the government of Arunachal Pradesh to “take appropriate action on Chakma and Hajong citizenship, as directed by the Supreme Court.”

The Supreme Court in its order dated 17 September, 2015, had directed “the government of India and the state of Arunachal Pradesh to finalise the conferment of citizenship rights on eligible Chakmas and Hajongs and also to ensure compliance of directions in judicial decisions... for protection of their life and liberty and against their discrimination in any manner, preferably within three months.”

Stating on a petition filed by Pritimoy Chakma on behalf of the Chakma and Hajong Elders’s Forum of Arunachal Pradesh and Suhas Chakma for the Chakma Development Foundation of India (CDFI) regarding non-compliance of the order passed by the Supreme Court in WP (civil) No 510/2007, the commission directed the union and the state governments to do the needful in case any part of the order of the Supreme Court still remains un-complied with and act accordingly.

The NHRC further directed that the Centre and the Arunachal government “shall take an early decision for providing the government welfare schemes to the affected persons and submit an action taken report in this regard to the commission within eight weeks.”

The two organisations had in March this year sought “extension of government social welfare schemes such as Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme, Chief Minister Arogya Arunachal Yojana/Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, etc, to the Chakma and Hajong senior citizens who have submitted citizenship applications or will submit citizenship applications.”

The organisations also sought that the Centre process 1,798 citizenship applications already forwarded by the Arunachal government “with or without enquiry” and also direct the deputy commissioners of Changlang, Namsai and Papum Pare to forward any remaining citizenship applications of the Chakmas and Hajongs “with or without enquiry,” as per the Supreme Court judgment on NHRC vs State of Arunachal Pradesh, to the home affairs ministry.

The NHRC further noted that the “additional solicitor general has fairly stated that the government of India will earnestly take appropriate measures in the matter, granted some more time.”

Suhas Chakma, one of the petitioners and founder of the CDFI in a statement said, “The registration of the complaint by the National Human Rights Commission as the original petitioner before the Supreme Court for protection of the rights of the Chakmas and Hajongs in 1995 is a historic one and a step in the right direction to address

disingenuous means adopted by the state of Arunachal Pradesh and union of India to not implement the Supreme Court judgments in the last 26 years to deny citizenship to the original migrants and further question the citizenship of their descendants and deny all the rights.”

He further said that, “when the state and non-state actors take pride for non-implementation of the Supreme Court judgments, there are serious problems whether the country itself is being governed by the rule of law.”

Chief Minister Pema Khandu had earlier said that the state government and the union government would work together on the Chakma-Hajong issue.

Addressing the people of the state on India’s 75th Independence Day, Khandu had said that “all illegal immigrant Chakmas will be moved and settled in some other places with honour, as per the constitution.”

The Chakmas and Hajongs, who were forced to flee the Chittagong Hill Tracts because of displacement following the construction of the Kaptai dam and because of religious persecution, were settled in Arunachal, starting in 1964, in designated camps in the present-day Papum Pare and Changlang districts.

Despite court orders, citizenship rights of the Chakma and Hajong settlers have been stiffly questioned and opposed by the All Arunachal Pradesh Students’ Union.

## **Rahul Bhat killing: Delhi Congress urges NHRC to provide protection to kin of Kashmiri Pandit**

<https://www.newindianexpress.com/nation/2022/may/20/rahul-bhat-killing-delhi-congress-urges-nhrc-to-provide-protection-to-kin-of-kashmiri-pandit-2455951.html>

The Delhi Congress submitted a memorandum to the NHRC on Friday, seeking protection for the family of Rahul Bhat, a Kashmiri Pandit who was recently shot dead by terrorists in Kashmir's Chadoora town.

A delegation from the Legal and Human Rights department of the Delhi Congress, led by advocate Sunil Kumar, met National Human Rights Commission (NHRC) Secretary General Devendra Kumar Singh and urged him to constitute a committee for the protection of Bhat's family, according to a statement issued by the party.

Kumar said the delegation urged the NHRC to direct the Jammu and Kashmir administration to pay a sum of Rs 1 crore as compensation to Bhat's widow and provide protection to Kashmiri Pandits and their families in the valley.

"We have also asked the NHRC to prepare a detailed report after visiting Jammu and Kashmir and provide safe residential premises to the Kashmiri Pandits who have been serving in various departments of the Jammu and Kashmir administration," he said.

Kumar said the delegation "brought to the attention of the NHRC that 14 people from the Hindu community were killed by terrorists in Jammu and Kashmir between August 2019 and March 2022".

The Union Territory administration has "failed" to ensure the safety and security of the Kashmiri Pandits, who migrated to the valley under a special package announced by the then Congress-led UPA government at the Centre in 2010, Kumar said.

Devdiscourse/LatestLY/NYOOOZ/ThePrint

## **Delhi Cong urges NHRC to provide protection to kin of of Kashmiri Pandit killed by terrorists in J&K**

<https://www.devdiscourse.com/article/law-order/2045098-delhi-cong-urges-nhrc-to-provide-protection-to-kin-of-kashmiri-pandit-killed-by-terrorists-in-jk>

<https://www.latestly.com/agency-news/india-news-delhi-cong-urges-nhrc-to-provide-protection-to-kin-of-kashmiri-pandit-killed-by-terrorists-in-jk-3730114.html>

<https://www.nyoooz.com/news/delhi/1677551/delhi-cong-urges-nhrc-to-provide-protection-to-kin-of-kashmiri-pandit-killed-by-terrorists-in-jk/>

<https://theprint.in/india/delhi-cong-urges-nhrc-to-provide-protection-to-kin-of-kashmiri-pandit-killed-by-terrorists-in-jk/964469/>

The Delhi Congress submitted a memorandum to the NHRC on Friday, seeking protection for the family of Rahul Bhat, a Kashmiri Pandit who was recently shot dead by terrorists in Kashmir's Chadoora town.

A delegation from the Legal and Human Rights department of the Delhi Congress, led by advocate Sunil Kumar, met National Human Rights Commission (NHRC) Secretary General Devendra Kumar Singh and urged him to constitute a committee for the protection of Bhat's family, according to a statement issued by the party.

Kumar said the delegation urged the NHRC to direct the Jammu and Kashmir administration to pay a sum of Rs 1 crore as compensation to Bhat's widow and provide protection to Kashmiri Pandits and their families in the valley.

"We have also asked the NHRC to prepare a detailed report after visiting Jammu and Kashmir and provide safe residential premises to the Kashmiri Pandits who have been serving in various departments of the Jammu and Kashmir administration," he said.

Kumar said the delegation "brought to the attention of the NHRC that 14 people from the Hindu community were killed by terrorists in Jammu and Kashmir between August 2019 and March 2022".

The Union Territory administration has "failed" to ensure the safety and security of the Kashmiri Pandits, who migrated to the valley under a special package announced by the then Congress-led UPA government at the Centre in 2010, Kumar said.



## **NHRC asks Centre, Arunachal govt to examine compliance of SC order on Chakma-Hajong citizenship**

<https://www.uniindia.com/story/NHRC-asks-Centre-Arunachal-govt-to-examine-compliance-of-SC-order-on-Chakma-Hajong-citizenship>

The National Human Rights Commission (NHRC) has directed the Centre and Arunachal Pradesh government to examine the compliance of order passed by the Supreme Court in 2015 to confer citizenship to the Chakmas and Hajongs within three months, and do the needful in case any part of the order of the Apex Court still remains "uncomplied" and inform the Commission within two months, Suhas Chakma, founder of Chakma Development Foundation of India (CDFI) on Friday claimed. He informed that the direction from the NHRC came after the CDFI and Chakma and Hajong Elders' Forum of Arunachal Pradesh (CHEF) filed a joint complaint with the Commission on March 22 stating that the 1996 and 2015 judgments of the Apex Court were not complied with as on date and not a single citizenship application out of the 4,637 applications submitted during 1997-2003 has been determined. "Hearings were held only in 3,827 applications out of which only 1,798 were forwarded by the State government of Arunachal Pradesh to the Ministry of Home Affairs but no decision has been taken in the last 26 years. Rule 12 of the Citizenship Rules, 2009 requires the Deputy Commissioner/State government to forward the citizenship applications within 120 days at the maximum," Chakma said. The SC in its order on September 17, 2015 had directed the Government of India and Arunachal Pradesh government to finalise the conferment of citizenship rights on eligible Chakmas and Hajongs, the CDFI founder claimed.

"The registration of complaint by the NHRC as the original petitioner before the SC for protection of the rights of the Chakmas and Hajongs in 1995 was a historic one. The non-implementation of the Apex Court's judgments shall go down in the annals of history as the worst case of 'racial discrimination'. When the state and nonstate actors take pride for non-implementation of the judgments, there are serious problems whether the country itself is being governed by the rule of law," Chakma said. Endorsing the CDFI founder, CHEF general secretary Pritimoy Chakma said, "All 1,798 applicants whose applications have been forwarded to the Central government had signed the oath of allegiance with incontrovertible documents such as AADHAR card, ration cards, police verification report, father's ID card, land possession certificate, land taxes paid etc. None of these applicants has any criminal cases against them and the police verification reports on their antecedents are clear. Descendants of most applicants such as son, daughters and children have been enrolled as voters based on the documents of the migrants but the original migrants' applications have not been processed." On Friday, a delegation of the CHEF and CDFI led by Suhas Chakma had met the NHRC officials and apprised various issues related to the Chakmas and Hajongs. Chief Minister Pema Khandu had, in his Independence Day address in 2021, stated that both the BJP Governments in the State and at the Centre will work "in a much focused way" and will relocate the illegal immigrants "with proper order" beyond Arunachal Pradesh. "Arunachal being a tribal state, as per constitutional provisions, they (Chakmas-Hajongs) cannot settle down in our state....We will solve this vexed issue

constitutionally, in coming days,” Khandu had said. Arunachal Pradesh Students' Union (AAPSU), the state's apex student organization, which has been spearheading a mass movement against the Chakmas and Hajongs for decades, demanded the ChakmaHajong settlers be shifted out of tribal-dominated Arunachal Pradesh. The AAPSU fears that the 'refugees' could outnumber the indigenous population and influence electoral outcomes. UNI DS SHK1919

## **NHRC issues notice to MP Govt on reports of attack on Dalit groom for riding horse in wedding procession**

<https://theprint.in/india/nhrc-issues-notice-to-mp-govt-on-reports-of-attack-on-dalit-groom-for-riding-horse-in-wedding-procession/964866/>

National Human Rights Commission (NHRC) India has taken a suo motu cognizance of a media report that a group of people attacked a groom belonging to a Scheduled Caste family while he was riding a horse during his own wedding procession in Rajgarh district of Madhya Pradesh on May 15, 2022, said a press release.

NHRC issued notices to the Chief Secretary and the Director-General of Police, Madhya Pradesh calling for a detailed report on the matter within four weeks including action taken against the miscreants and compensation granted to the aggrieved family.

Reportedly, they were opposed to the groom riding a horse and using a DJ in the wedding procession and the brother of the bride had already requested security from the police in view of the threats.

The Commission has observed that the contents of the media report, if true, amount to a violation of the human rights of victims.

The Commission has also observed that in a civilized society, such inhuman incidents are required to be strictly condemned and the perpetrators are liable to be adequately reprimanded and brought to law.

There are special legal provisions for the protection of the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and other vulnerable sections of the society from such harassment and humiliation but in spite of that such incidents occur frequently in different parts of the country amounting to a violation of human rights. (ANI)

ANI News/ ThePrint/ Devdiscourse/ LatestLY/ Big News Network.com

## **NHRC takes suo motu cognizance over murder of inmate of Juvenile Home in Jaipur**

<https://www.aninews.in/news/national/general-news/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-over-murder-of-inmate-of-juvenile-home-in-jaipur20220520213729/>

<https://theprint.in/india/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-over-murder-of-inmate-of-juvenile-home-in-jaipur/964750/>

<https://www.devdiscourse.com/article/law-order/2045319-nhrc-takes-suo-motu-cognizance-over-murder-of-inmate-of-juvenile-home-in-jaipur>

<https://www.latestly.com/agency-news/india-news-nhrc-takes-suo-motu-cognizance-over-murder-of-inmate-of-juvenile-home-in-jaipur-3730728.html>

<https://www.bignewsnetwork.com/news/272559367/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-over-murder-of-inmate-of-juvenile-home-in-jaipur>

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken a suo motu cognizance of a media report that a 20-year-old inmate who was killed by fellow inmates in Jaipur's Transport Nagar Juvenile Home in Rajasthan on May 17, 2022, said a press release. Reportedly, he was killed in the night and the incident was noted in the morning. The CCTV cameras installed in the juvenile home were also not working, added the press release.

The Commission has observed that the contents of the media report, if true, amount to a violation of the human rights of the victim who was in the custody of the State. Accordingly, it has issued a notice to the Chief Secretary and the Director-General of Police, Rajasthan calling for a detailed report on the matter within four weeks, as per the statement. The report is expected to include action against the negligent public servants and the status of the FIR registered in the matter. It should also contain the outcome of proceedings of the JJ Board and its follow up by the State authorities. The Commission would also like to know if any relief/ compensation has been announced/ given to the NOK of the deceased by the state authorities. Issuing the notices, the Commission has also observed that going by the media report, it appears, that the deceased had attained the age of 20 years. He should have been shifted to the jail instead of a juvenile home. Secondly, the victim was allegedly hit by an iron rod in the night and after his death, his body was recovered the next day it shows that there were no proper security arrangements made by the authorities, inside the juvenile home due to which the perpetrators could kill the victim without any fear of law in their mind.

## **NHRC issues Raj Govt notice over murder of inmate at juvenile home in Jaipur**

<https://www.uniindia.com/story/NHRC-issues-Raj-Govt-notice-over-murder-of-inmate-at-juvenile-home-in-Jaipur>

) Taking a suo moto cognizance of the murder of a 20-year-old Juvenile Home inmate who was reportedly killed by fellow inmates in Jaipur, Rajasthan a few days ago, the National Human Rights Commission (NHRC) on Friday issued a notice to Rajasthan Government seeking a detailed report on the matter. The NHRC said it came to know about the incident through media reports and asked the Chief Secretary and the Director-General of Police, Rajasthan, to submit the report within four weeks. Issuing the notices, the human rights body also observed that the deceased had attained the age of 20 years and should have been shifted to the jail instead of a juvenile home, it said mentioning the media reports. "The Commission has observed that the contents of the media report, if true, amount to a violation of human rights of the victim who was in the custody of the State. Accordingly, it has issued a notice to the Chief Secretary and the Director-General of Police, Rajasthan calling for a detailed report on the matter within four weeks," it said in a statement issued. According to the commission, the boy was reportedly killed on Tuesday night and the incident was noted the next day in the morning. "It shows that there were no proper security arrangements made by the authorities, inside the juvenile home due to which the perpetrators could kill the victim without any fear of law in their mind. The CCTV cameras installed in the juvenile home were also not working," the NHRC noted. Meanwhile, the Commission said that it expects the report to include action against the negligent public servants and the status of the FIR registered in the matter. It should also n the outcome of proceedings of the JJ Board and its follow up by the State authorities. The Commission would also like to know if any relief/ compensation has been announced/ given to the NOK of the deceased by the state authorities," the statement by NHRC said. UNI ASHNHRC issues Raj Govt notice over murder of inmate at juvenile home in Jaipur New Delhi, May 20 (UNI): Taking a suo moto cognizance of the murder of a 20-year-old Juvenile Home inmate who was reportedly killed by fellow inmates in Jaipur, Rajasthan a few days ago, the National Human Rights Commission (NHRC) on Friday issued a notice to Rajasthan Government seeking a detailed report on the matter. The NHRC said it came to know about the incident through media reports and asked the Chief Secretary and the Director-General of Police, Rajasthan, to submit the report within four weeks. Issuing the notices, the human rights body also observed that the deceased had attained the age of 20 years and should have been shifted to the jail instead of a juvenile home, it said mentioning the media reports. "The Commission has observed that the contents of the media report, if true, amount to a violation of human rights of the victim who was in the custody of the State. Accordingly, it has issued a notice to the Chief Secretary and the Director-General of Police, Rajasthan calling for a detailed report on the matter within four weeks," it said in a statement issued. According to the commission, the boy was reportedly killed on Tuesday night and the incident was noted the next day in the morning. "It shows that there were no proper security arrangements made by the authorities, inside the juvenile home due to which the perpetrators could kill the victim



without any fear of law in their mind. The CCTV cameras installed in the juvenile home were also not working," the NHRC noted. Meanwhile, the Commission said that it expects the report to include action against the negligent public servants and the status of the FIR registered in the matter. It should also contain the outcome of proceedings of the JJ Board and its follow up by the State authorities. The Commission would also like to know if any relief/ compensation has been announced/ given to the NOK of the deceased by the state authorities," the statement by NHRC said.

## **NHRC takes suo motu cognisance over murder of 20-year old inmate of Jaipur's Juvenile Home**

<https://www.republicworld.com/india-news/general-news/nhrc-takes-suo-motu-cognisance-over-murder-of-20-year-old-inmate-of-jaipurs-juvenile-home-articleshow.html>

Taking suo moto cognisance of the murder of a 20-year-old Transport Nagar Juvenile Home inmate, who was reportedly killed by fellow inmates in Jaipur, the National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Rajasthan government seeking a detailed report in the matter. Reportedly, he was killed in the night and the incident was noted in the morning.

NHRC issues notice to Rajasthan government in Jaipur's 20-year-old murder case  
The Commission said that it learnt about the incident through media reports and further asked the Chief Secretary and the Director-General of Rajasthan Police to submit the report within four weeks. NHRC observed that if the contents of the media report were true, it would amount to violation of the human rights of the victim who was in the State's custody. In the notice, the Commission also stated that the deceased had attained the age of 20 years and should have been shifted to the jail instead of a juvenile home, citing the media reports.

The statement read, "The Commission has observed that the contents of the media report, if true, amount to a violation human rights of the victim who was in the custody of the State. Accordingly, it has issued a notice to the Chief Secretary and the Director-General of Police, Rajasthan calling for a detailed report on the matter within four weeks."

NHRC added, "The victim was allegedly hit by an iron rod in the night and after his death, his body was recovered the next day it shows that there were no proper security arrangements made by the authorities, inside the juvenile home due to which the perpetrators could kill the victim without any fear of law in their mind. The CCTV cameras installed in the juvenile home were also not working."

Additionally, the human rights body has said that it expects the report to include action against the negligent public servants and the status of the FIR registered in the matter. It stated that the report should also include the outcome of proceedings of the JJ Board and its follow-up by the State authorities. "The Commission would also like to know if any relief/compensation has been announced/given to the NOK of the deceased by the state authorities," the statement said.

## **NHRC takes suo motu cognisance over murder of 20-year old inmate of Jaipur s Juvenile Home**

<https://www.republicworld.com/india-news/general-news/nhrc-takes-suo-motu-cognisance-over-murder-of-20-year-old-inmate-of-jaipurs-juvenile-home-articleshow.html>

Taking suo moto cognisance of the murder of a 20-year-old Transport Nagar Juvenile Home inmate, who was reportedly killed by fellow inmates in Jaipur, the National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Rajasthan government seeking a detailed report in the matter. Reportedly, he was killed in the night and the incident was noted in the morning.

NHRC issues notice to Rajasthan government in Jaipur's 20-year-old murder case  
The Commission said that it learnt about the incident through media reports and further asked the Chief Secretary and the Director-General of Rajasthan Police to submit the report within four weeks. NHRC observed that if the contents of the media report were true, it would amount to violation of the human rights of the victim who was in the State's custody. In the notice, the Commission also stated that the deceased had attained the age of 20 years and should have been shifted to the jail instead of a juvenile home, citing the media reports.

The statement read, "The Commission has observed that the contents of the media report, if true, amount to a violation human rights of the victim who was in the custody of the State. Accordingly, it has issued a notice to the Chief Secretary and the Director-General of Police, Rajasthan calling for a detailed report on the matter within four weeks."

NHRC added, "The victim was allegedly hit by an iron rod in the night and after his death, his body was recovered the next day it shows that there were no proper security arrangements made by the authorities, inside the juvenile home due to which the perpetrators could kill the victim without any fear of law in their mind. The CCTV cameras installed in the juvenile home were also not working."

Additionally, the human rights body has said that it expects the report to include action against the negligent public servants and the status of the FIR registered in the matter. It stated that the report should also include the outcome of proceedings of the JJ Board and its follow-up by the State authorities. "The Commission would also like to know if any relief/compensation has been announced/given to the NOK of the deceased by the state authorities," the statement said.

जांच आयोग ने माना, पुलिस को मालूम था कि गोली चलाने से आरोपियों की मौत हो जाएगी, बयान मनगढ़ंत

# हैदराबाद दुष्कर्म मामले में मुठभेड़ फर्जी

## खुलासा

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। हैदराबाद में 25 वर्षीय पशु चिकित्सक दिशा (बदला हुआ नाम) से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में मुठभेड़ को सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त जांच आयोग ने फर्जी करार दिया है।

पुलिस के दावों को अविश्वसनीय बताते हुए जांच आयोग ने शुक्रवार को कहा कि पुलिस ने आरोपियों को जानबूझकर गोली मारी। जस्टिस सिरपुरकर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय आयोग ने उच्चतम न्यायालय से मुठभेड़ में शामिल सभी दस पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा चलाने की सिफारिश की है।

दिसंबर 2019 की कथित हैदराबाद मुठभेड़ में हत्याओं की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वीएस सिरपुरकर की अध्यक्षता वाले आयोग ने पाया है कि संदिग्धों की मौत पुलिस की गोलियों से हुई। पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षा या मृतक संदिग्धों को फिर से गिरफ्तार करने के प्रयास में गोली



हैदराबाद में पशु चिकित्सक से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में इसी जगह मुठभेड़ में आरोपी मारे गए थे। • फाइल फोटो

नहीं चलाई थी, बल्कि पुलिस को मालूम था कि गोली चलाने से आरोपियों की मौत हो जाएगी। आरोपियों के शरीर पर जख्म के सभी निशान कमर के ऊपर मिले। इससे यह पुष्ट होता है कि सामने की ओर से गोली मारी गई।

## तुरंत न्याय का विचार अस्वीकार्य

आगे क्या प्रक्रिया होनी चाहिये, इसके बारे में कुछ सिफारिशें करते हुए आयोग ने कहा कि जिस तरह मॉब लिंचिंग अस्वीकार्य है, उसी तरह तत्काल न्याय का कोई विचार भी अस्वीकार्य है। कानून का शासन कायम होना चाहिए। अपराध के लिए सजा केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना राज्य की मांग को खारिज करते हुए आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की अनुमति दी थी।

**27** नवंबर 2019 को 25 वर्षीय पशु चिकित्सक का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई

**29** नवंबर, 2019 को चारों आरोपियों मोहम्मद आरिफ, चिंटाकुंटा चेन्नाकेश्वरु, जोलु शिवा और जोलु नवीन पकड़े गए

■ 06 दिसंबर को पुलिस चारों आरोपियों को हैदराबाद के पास एनएच-44 पर हुए घटनास्थल पर ले जा रही थी, इसी राजमार्ग पर 27 वर्षीय युवती का जला हुआ शव मिला था

■ तेलंगाना पुलिस ने कहा था कि सभी आरोपी मुठभेड़ में मारे गए। यह घटना सुबह करीब साढ़े छह बजे हुई थी

■ समिति का गठन करते हुए उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में चल रहे मुकदमों की सुनवाई पर रोक लगा दी थी



## हैदराबाद मुठभेड़ : जांच रिपोर्ट तेलंगाना हाईकोर्ट को भेजी

■ नई दिल्ली (भाषा)।

उच्चतम न्यायालय ने हैदराबाद में एक पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक दुष्कर्म तथा हत्या मामले के चार आरोपियों की कथित मुठभेड़ की जांच से संबंधित आयोग की सीलबंद रिपोर्ट को साझा करने का शुक्रवार को आदेश दिया तथा आगे की कार्रवाई के लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय के पास भेज दिया।

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान के उस अनुरोध को ठुकरा दिया कि तीन-सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में रखी जाए। पीठ ने कहा, यह (रिपोर्ट) मुठभेड़ मामले से संबद्ध है। इसमें यहां रखने जैसी कोई बात नहीं है। आयोग ने किसी को दोषी पाया है। हम मामले को उच्च न्यायालय के पास भेजना चाहते हैं। हमें मामले को वापस उच्च न्यायालय के पास भेजना पड़ेगा, हम इस मामले की निगरानी नहीं कर सकते। एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी गई है। सवाल यह है कि क्या उचित कार्रवाई की जाए। उन्होंने कुछ सिफारिशें की हैं।

■ सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों से भी रिपोर्ट साझा करने का दिया आदेश

■ पशु चिकित्सक के रेप व मर्डर के चारों आरोपियों के एनकाउंटर का मामला

पीठ ने कहा, हम आयोग सचिवालय को दोनों पक्षों को रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश देते हैं। इससे पहले पीठ ने आयोग की सीलबंद लिफाफे वाली रिपोर्ट कुछ वक्त के लिए वकीलों के साथ साझा करने से इनकार कर दिया था। चार आरोपियों के मुठभेड़ में मारे जाने की जांच कर रहे आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश वी एस सिरपुरकर ने की है। हालांकि, न्यायालय ने रजिस्ट्री को पीठ के न्यायाधीशों को रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। सीजेआई ने वकीलों के साथ कुछ वक्त के लिए रिपोर्ट साझा न करने का निर्देश देते हुए कहा था, पहले हमें रिपोर्ट पढ़ने दीजिए। इससे पहले शीर्ष न्यायालय ने

गत वर्ष तीन अगस्त को आयोग को मुठभेड़ मामले पर अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए छह महीने का और समय दिया था।

सिरपुरकर समिति का गठन 12 दिसंबर 2019 को हुआ था और उसे उन परिस्थितियों की जांच करने का जिम्मा सौंपा गया, जिसके चलते मुठभेड़ हुई। उसे अपनी रिपोर्ट छह महीने में सौंपनी थी। समिति का गठन करते हुए उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में चल रहे मुकदमों की सुनवाई पर रोक लगा दी थी।

तेलंगाना पुलिस ने कहा था कि आरोपी मुठभेड़ में मारे गए। यह घटना सुबह करीब साढ़े छह बजे हुई थी जब आरोपियों को जांच के लिए घटनास्थल ले जाया जा रहा था। चारों आरोपियों मोहम्मद आरिफ, चिटाकुंटा चेनाकेश्वरु, जोलु शिवा और जोलु नवीन को नवंबर 2019 में एक पशु चिकित्सक के सामूहिक दुष्कर्म तथा हत्या मामले में पकड़ा गया था। चारों आरोपियों को हैदराबाद के समीप एनएच-44 पर कथित मुठभेड़ में गोली मार दी गई थी। इसी राजमार्ग पर 27 वर्षीय युवती का जला हुआ शव मिला था।



# हैदराबाद मुठभेड़ : जांच रिपोर्ट तेलंगाना हाईकोर्ट को भेजी

■ नई दिल्ली (भाषा)।

उच्चतम न्यायालय ने हैदराबाद में एक पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक दुष्कर्म तथा हत्या मामले के चार आरोपियों की कथित मुठभेड़ की जांच से संबंधित आयोग की सीलबंद रिपोर्ट को साझा करने का शुक्रवार को आदेश दिया तथा आगे की कार्रवाई के लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय के पास भेज दिया।

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान के उस अनुरोध को ठुकरा दिया कि तीन-सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में रखी जाए। पीठ ने कहा, यह (रिपोर्ट) मुठभेड़ मामले से संबद्ध है। इसमें यहां रखने जैसी कोई बात नहीं है। आयोग ने किसी को दोषी पाया है। हम मामले को उच्च न्यायालय के पास भेजना चाहते हैं। हमें मामले को वापस उच्च न्यायालय के पास भेजना पड़ेगा, हम इस मामले की निगरानी नहीं कर सकते। एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी गई है। सवाल यह है कि क्या उचित कार्रवाई की जाए। उन्होंने कुछ सिफारिशें की हैं।

■ सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों से भी रिपोर्ट साझा करने का दिया आदेश

■ पशु चिकित्सक के रेप व मर्डर के चारों आरोपियों के एनकाउंटर का मामला

पीठ ने कहा, हम आयोग सचिवालय को दोनों पक्षों को रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश देते हैं। इससे पहले पीठ ने आयोग की सीलबंद लिफाफे वाली रिपोर्ट कुछ वक्त के लिए वकीलों के साथ साझा करने से इनकार कर दिया था। चार आरोपियों के मुठभेड़ में मारे जाने की जांच कर रहे आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश वी एस सिरपुरकर ने की है। हालांकि, न्यायालय ने रजिस्ट्री को पीठ के न्यायाधीशों को रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। सीजेआई ने वकीलों के साथ कुछ वक्त के लिए रिपोर्ट साझा न करने का निर्देश देते हुए कहा था, पहले हमें रिपोर्ट पढ़ने दी जाए। इससे पहले शीर्ष न्यायालय ने

गत वर्ष तीन अगस्त को आयोग को मुठभेड़ मामले पर अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए छह महीने का और समय दिया था।

सिरपुरकर समिति का गठन 12 दिसंबर 2019 को हुआ था और उसे उन परिस्थितियों की जांच करने का जिम्मा सौंपा गया, जिसके चलते मुठभेड़ हुई। उसे अपनी रिपोर्ट छह महीने में सौंपनी थी। समिति का गठन करते हुए उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में चल रहे मुकदमों की सुनवाई पर रोक लगा दी थी।

तेलंगाना पुलिस ने कहा था कि आरोपी मुठभेड़ में मारे गए। यह घटना सुबह करीब साढ़े छह बजे हुई थी जब आरोपियों को जांच के लिए घटनास्थल ले जाया जा रहा था। चारों आरोपियों मोहम्मद आरिफ, चिटकुटा चेन्नाकेश्वुलु, जोलु शिवा और जोलु नवीन को नवंबर 2019 में एक पशु चिकित्सक के सामूहिक दुष्कर्म तथा हत्या मामले में पकड़ा गया था। चारों आरोपियों को हैदराबाद के समीप एनएच-44 पर कथित मुठभेड़ में गोली मार दी गई थी। इसी राजमार्ग पर 27 वर्षीय युवती का जला हुआ शव मिला था।

## कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए याचिका दायर

नई दिल्ली। दिल्ली कांग्रेस ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की। प्रदेश कांग्रेस के विधिक एवं मानवाधिकार विभाग के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सेक्रेटरी जनरल के समक्ष दायर याचिका में पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया करने सहित मुआवजा राशि बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने की गुहार लगाई है। जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों ने 12 मई को सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या कर दी थी। विधिक एवं मानवाधिकार विभाग के चेयरमैन सुनील कुमार ने कहा कि जम्मू - कश्मीर के बड़गाम जिले के चदूरा में तहसील कार्यालय के अंदर आतंकवादियों ने सरकारी कर्मचारी व कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को गोली मारकर कर दी थी।

**NHRC issues advisory to authorities  
for environmental pollution**

The National Human Rights Commission, NHRC, India, headed by Justice Arun Kumar Mishra, has issued an Advisory to the Centre and the State Governments to prevent, minimise and mitigate the impacts of Environmental Pollution and Degradation on Human Rights. The Commission has finalised the Advisory in consultation with the domain experts by examining the effects of air & water pollution and ecological degradation on enjoyment of basic human rights.



# In austerity drive, CEC, ECs decide to forgo tax perks

Bharti.Jain@timesgroup.com

**New Delhi:** Setting an example by embracing austerity in personal entitlements, the Election Commission on Friday decided that the chief election commissioner and election commissioners will forgo income-tax benefits available to them on sumptuary allowance besides availing only one leave travel concession (LTCs) in a year instead of the three entitled so far.

The decision came at the very first meeting of the full Commission — which currently has only two members — chaired by CEC Rajiv Kumar, who took charge on May 15.

Kumar — who had retired as the finance services secretary — was keen that as a Constitutional authority, EC should take the lead by giving up benefits and allowances that cause an unnecessary and avoidable burden on the exchequer, sources said. Observers said the measure may end up being a permanent one, as subsequent CECs and election commissioners may be under moral pressure not to undo the financially prudent measure.

Similar perks and benefits are available to Su-



PTI

The decision came at the first meeting of the full commission chaired by CEC Rajiv Kumar, who took charge on May 15

preme Court judges, with whom CEC and election commissioners enjoy pay parity; as well as members of other statutory bodies such as NHRC and Lok Pal.

The CEC and election commissioners are entitled to a monthly sumptuary allowance of Rs 34,000 on which no income tax is payable. On Friday, the Commission, feeling the need to observe austerity in personal entitlements, decided that CEC and election commissioners will not take the income tax benefits presently available to them. A proposal in this regard will be sent to the central government for appropriate action. It was also decided that CEC and election commissioners will avail one LTC in a year.

## Houses razed in MP after pelting at Dalit's baraat

**Bhopal:** More than 48 houses were bulldozed by government authorities in Ragharh district of Madhya Pradesh on Friday, hours after they were served notices stating they had encroached on government properties. The action came two days after the marriage procession of a Dalit was pelted with stones. Of the total houses demolished, 18 belonged to people accused of throwing stones at the marriage procession.

There was an altercation between members of a community and those taking part in the wedding procession over playing of loud music as the procession passed near a religious place. Immediately after an FIR was registered, residents were issued notices claiming they had encroached on government land. TNN



## कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने की मांग

नई दिल्ली। दिल्ली कांग्रेस के विधिक एवं मानवाधिकार विभाग ने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की है। शुक्रवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। कांग्रेस नेता और एडवोकेट सुनील कुमार ने उच्चस्तरीय समिति का गठन करने की मांग की, जो जम्मू-कश्मीर का दौरा कर यह सुझाव दे कि सरकारी विभागों में काम कर रहे कश्मीरी पंडितों को कैसे सुरक्षा मुहैया कराई जा सके।

# Panel had questioned Bhagwat report

**MOULI MAREEDU | DC**  
HYDERABAD, MAY 20

The Justice V.S. Sirpurkar Commission took into consideration the depositions of the Special Investigation Team (SIT) in connection with the CCTVs functioning at Shadnagar police station and weapons at the scene of offence.

In the report, the commission said Rachakonda police commissioner Mahesh Bhagwat, SIT head, had stated that on December 11, 2019, when the team visited the scene, investigation officer J. Surender Reddy had informed them that the articles belonging to Disha were recovered from the 5th bund at the

scene of occurrence. The police party had also fired from the 5th bund.

The commission said that a question arose as to how the SIT had concluded in its final report that the recoveries of articles of Disha were effected from the lower side of the middle portion of the 5th embankment.

With regard to weapons, the commission said that the SIT reported the position of the 'selector switch' on the AK-47 rifle used by Shaik Lal Madhar or the position of safety latch on the 9MM pistols recovered from the Disha case suspects Mohammed Arif and Chintakunta Chennakeshavulu were

not investigated by the police; the position was not recorded in the panchanama or the seizure panchanama. It was further stated that the SIT did not examine the panchanama regarding the position of the selector switch.

The commission examined the records of the Special Investigation Team in Crime No.803, of the NHRC investigation team, the post-mortem examination reports, forensic reports, call data records and the 1,441 affidavits received from various persons including the police, relatives of the deceased, forensic experts and the like.

Pinjari Hussain, the father of Arif,

Chintakunta Renuka, the wife of Chintakunta Chennakeshavulu, Jollu Laxmi, the mother of Jollu Naveen, and Jollu Rajaiah, the father of Jollu Shiva, had stated in their affidavits that the police had killed the suspects in an encounter.

Replying to a question on whether CCTV cameras were installed and not working, or were they never installed at the Shadnagar police station, Bhagwat stated that investigating officer Surender Reddy could not get any reply from the SHO, Shadnagar. According to the commission, the SIT said no such recordings were recovered from the Shadnagar police station because by

the time the collection started its storage capacity was exhausted.

The photographs and videos produced by the SIT as well as the media houses showed that there was no large crowd present at the scene of the incident on December 6, 2019. The crowd that was present was confined to the national highway, about 500 metres from the scene.

The videos do not show the crowd interfering with the investigation procedures. The commission was forced to collect the videos and photos taken by the media as the SIT did not furnish the complete collection, according to the SC-mandated report.

# CEC, ECs decide to forgo tax benefit on allowances

**Bharti.Jain@timesgroup.com**

**New Delhi:** Setting an example by embracing austerity in personal entitlements, the Election Commission on Friday decided that the chief election commissioner and election commissioners will forgo income-tax benefits available to them on sumptuary allowance besides availing only one leave travel concession (LTCs) in a year instead of the three entitled so far. The decision came at the very first meeting of the full commission — which presently has only two members — chaired by CEC Rajiv Kumar, who took charge on May 15.

Kumar — who had retired as the finance services

secretary — was keen that as a constitutional authority, EC should take the lead by giving up benefits and allowances that cause an unnecessary and avoidable burden on the exchequer, sources said. Observers said the measure may end up being a permanent one, as subsequent CECs and election commissioners may be under moral pressure not to undo the financially prudent measure.

Similar perks and benefits are available to Supreme Court judges, with whom CEC and election commissioners enjoy pay parity; as well as members of other statutory bodies such as NHRC and Lok Pal.

*Full report on [www.toi.in](http://www.toi.in)*



# In austerity drive, CEC, ECs decide to forgo tax perks

PTI

Bharti.Jain@timesgroup.com

**New Delhi:** Setting an example by embracing austerity in personal entitlements, the Election Commission on Friday decided that the chief election commissioner and election commissioners will forgo income-tax benefits available to them on sumptuary allowance besides availing only one leave travel concession (LTCs) in a year instead of the three entitled so far.

The decision came at the very first meeting of the full Commission — which currently has only two members — chaired by CEC Rajiv Kumar, who took charge on May 15.

Kumar — who had retired as the finance services secretary — was keen that as a Constitutional authority, EC should take the lead by giving up benefits and allowances that cause an unnecessary and avoidable burden on the exchequer, sources said. Observers said the measure may end up being a permanent one, as subsequent CECs and election commissioners may be under moral pressure not to undo the financially prudent measure.

Similar perks and benefits are available to Su-



The decision came at the first meeting of the full commission chaired by CEC Rajiv Kumar, who took charge on May 15

preme Court judges, with whom CEC and election commissioners enjoy pay parity; as well as members of other statutory bodies such as NHRC and Lok Pal.

The CEC and election commissioners are entitled to a monthly sumptuary allowance of Rs 34,000 on which no income tax is payable. On Friday, the Commission, feeling the need to observe austerity in personal entitlements, decided that CEC and election commissioners will not take the income tax benefits presently available to them. A proposal in this regard will be sent to the central government for appropriate action. It was also decided that CEC and election commissioners will avail one LTC in a year.

---

## Stone pelting on baraat: 48 houses razed

**Bhopal:** More than 48 houses, 18 of them belonging to people against whom FIR has been lodged for stone pelting on a dalit's wedding procession were bulldozed by government authorities in Ragharh district of Madhya Pradesh on Friday. The action followed hours after they were served notices stating they had encroached on government properties.

**NHRC notices to CS, DGP:** Meanwhile the National Human Rights Commission, NHRC, has taken a suo motu cognizance of a media report about the attack on wedding procession. It has issued notices to the chief secretary and the director general of police, MP calling for a detailed report within four weeks. TNN